दैनिक जागरण, भोपाल 10 JAN 2011

अब घर में प्रसव कराने पर भी पैसा देगी सरकार

शशिकान्त तिवारी, भोपाल

प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। घर में प्रसव कराने वाली महिलाओं को भी पांच सौ रुपए दिए जाएंगे। यह राशि इसलिए दी जा रही है कि पैसे की कमी के चलते गर्भावस्था में जरूरी जांचे व उपचार प्रभावित नहीं हो।

◆ गर्भवती महिला के खानपान व जांच पर खर्च होगी राशि, जननी सुरक्षा योजना के मद से दी जाएगी राशि

साथ ही गर्भवती महिला के खान-पान पर भी यह राशि खर्च की जा सकेगी। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं ने इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिए हैं।

अभी सरकार जननी सुरक्षा योजना के तहत अस्पताल में प्रसव कराने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन के तौर पर 1400 रुपए देती है। साथ ही 600 रुपए प्रेरक को दिए जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में यह राशि क्रमशः 1000 और 200 है। जागरूकता की कमी के चलते करीब बीस फीसदी महिलाएं अस्पताल नहीं पहुंच रही हैं और घरों में ही प्रसव हो रहे हैं। इससे जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा रहता है। यहां तक कि गरीबी के चलते ये गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व जरूरी तीन जांचे भी नहीं कराती हैं। साथ ही गर्भावस्था के दौरान जरूरी खान-पान के अलावा आयरन, विटामिन व मिनरल्स की खुराक भी नहीं लेती हैं। इससे उन्हें खून की कमी के साथ ही अनेक बीमारियां घेर लेती हैं। अगर प्रसव अस्पताल में हुआ तब तो स्थिति कुछ हद तक संभाली जा सकती है, लेकिन घर में प्रसव होने की स्थिति में यह खतरनाक हो सकता है। अब सरकार की योजना है कि प्रसव के दो महीने पहले पांच सौ रुपए आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से गर्भवती महिला को मिल जाएंगे। अगर यह महिला अस्पताल में प्रसव कराती है तो जननी सुरक्षा योजना की 1400 व 1000 की राशि से पहले दिए गए पांच सौ रुपए काटकर शेष राशि भी प्रसूता को दे दी जाएगी।

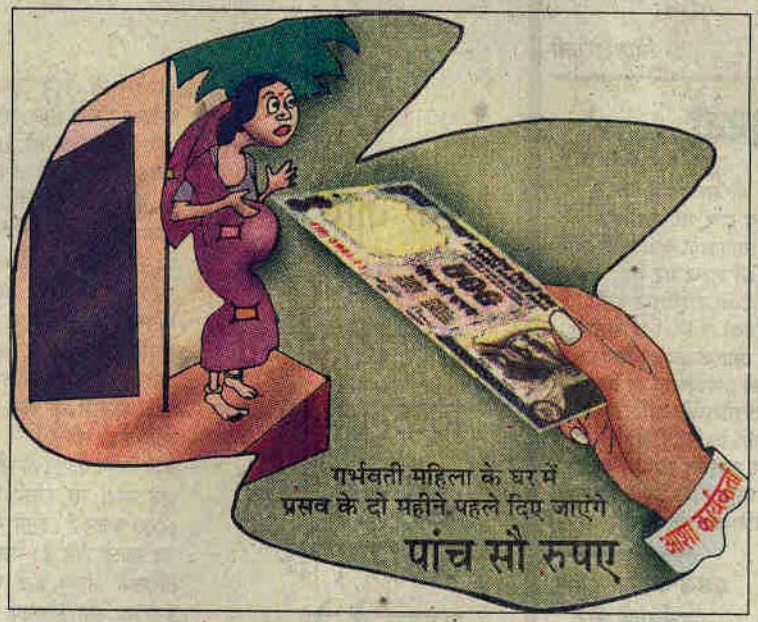

सामाजिक सरोकार

आईएमआर और एमएमआर कम करने के लिए पांच सौ रुपए गर्भवती महिला के घर में प्रसव के दो महीने पहले दिए जाएंगे। इसके सर्कुलर जारी कर दिए गए हैं।

डा. एएन मित्तल
संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं

प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 70 प्रति हजार है, जो देश में सर्वाधिक है। इसी तरह मातृ मृत्यु दर 379 प्रति एक लाख है। इन दोनों को रोकने संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए जननी सहयोगी, जननी सुरक्षा व प्रसव परिवहन योजना शुरू की गई है, ताकि अधिकांश प्रसव अस्पतालों में ही हों। इसके अलावा मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सेंटर शुरू किए जा रहे हैं। यहां पर ऐसी व्यवस्था रहेगी कि बीस मिनट के भीतर अस्पताल पहुंचा जा सकेगा।